

A representation opposing shifting of headquarters of Hindustan Copper Limited outside Rajasthan, was received from the Government of Rajasthan and they were informed on the lines indicated above.

12 NOON

**RE: STARRED QUESTION NO. 121
ANSWERED ON THE 4TH AUGUST, 1972**

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): Sir, in reply to a supplementary on Starred Question No. 121 answered on August 4, 1972, I had stated that "anybody leaving the country has to have an exit permit." The correct position is that a foreigner is required to obtain exit permit in all cases except the following:—

- (i) A tourist or non-tourist coming on a visa of up to three months is not required to obtain exit permit provided he leaves within three months.
- (ii) A tourist who gets extension for another three months is not required to obtain exit permit up to a total of six months,

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS OF MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : Sir, I beg to lay on the Table :—

- (i) A copy (in English and Hindi) each of the Ministry of External Affairs Notifications G.S.R. Nos. 34(E) and 35(E), dated the 20th January 1972, together with an erratum to the Hindi version of the notifications, under section 35 of the Extradition Act, 1962. [Placed in library. *See* No. LT-3408/72]

- (ii) A copy (in English and Hindi) each of the Ministry of External Affairs Notifications G.S.R. Nos. 285(E) and 286(E), dated the 25th May, 1972 issued under section 21 of the Passports Act, 1967.

- (iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of External Affairs Notification G.S.R. No. 317(E), dated the 19th June, 1972, publishing the Passports (Second Amendment) Rules, 1972, under sub-section (3) of section 24 of the Passports Act, 1967.

[Placed in Library. *See* No. 3407/42 for (i) and (ii)]

ANNUAL ACCOUNTS (1967-68) OF THE EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION AND RELATED PAPERS

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI BALGOVIND VERMA): Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) each of the following papers :—

- (i) Annual Accounts of the Employees' Provident Fund Organisation for the year 1967-68, and the Audit Report thereon.
- (ii) Statement giving reasons for the delay in laying on the Table the paper mentioned at (i) above. [Placed in Library. *See* No. LT-3449/72 for (i) and (ii)]

**CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE
REPORTED HEAVY LOSS SUSTAINED BY THE
SUPER BAZAR, DELHI**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) :
श्रीमान्, दिल्ली के सुपर बाजार को पिछले
कुछ वर्षों के दौरान कुप्रबन्ध के कारण हुई भारी

हानि के समाचार और इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों की ओर मैं कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHAB SHINDE) : Sir, it is true that the Super Bazar has incurred losses since its inception in July, 1966. Some of the main reasons for the losses incurred by the Super Bazar are that it had to incur initially a large amount of promotional and developmental expenditure and the rent paid for the building occupied by its largest branch in Connaught Circus was too high to be economical for a cooperative department store. Its overhead expenses were also high and the incidence of pilferages and shortages was considerable in the initial stages. Besides, there was a reduction in the size of its business in subsequent years, on account of comparatively easy availability of consumer goods in the market.

Remedial measures for improving the working of the Super Bazar have continuously been taken since 1967-68. Its business and accounting procedures have been considerably streamlined and further improvements are being made. By undertaking sale of high margin goods, it has steadily improved its percentage of gross profit. Arrangements have been made to earn additional income by proper utilisation of surplus space and by means of window display and advertisements. Some sections, which were incurring losses, have been leased out on fixed commissions to other parties. Special security staff has been engaged to assist in controlling pilferages and thefts, and this together with internal checks, has resulted in substantial reduction in shortages. The staff strength has been reduced from about 1,091 in June, 1967, to about 850 now, and other

measures of economy are also being implemented. In March, 1971, additional financial assistance amounting to Rs. 65 lakhs was given to the Super Bazar to enable it to liquidate its pressing liabilities and replenish stocks. The Super Bazar has reduced the size of its bank borrowings and maintains an adequate range and variety of stocks to meet the common requirements of consumers. Revised terms for the rental of the building in Connaught Circus are also being negotiated. During 1971-72 also financial assistance amounting to Rs. 5 lakhs has been given to the Super Bazar to enable it to undertake activities that will help to improve its business and economic viability. Concerted efforts are being made by the management of the Super Bazar so that it may be able to break even and attain economic viability.

Hon. Members will appreciate the importance of cooperative movement in the interest of consumers. Government is aware of the problems and shortcomings of the super bazar, and Government propose to take all necessary steps to ensure that this cooperative enterprise succeeds and renders valuable service to the community at large.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) : What is the total loss incurred so far ?

SHRI ANNASAHAB SHINDE : I am prepared to give if the Chair permits me.

SHRI MAHAVIR TYAGI : You have not given the figures.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सुपर बाजार की सहकारिता के क्षेत्र में एक प्रयोग के रूप में कोमलों को कम करने की दृष्टि से जो एक योजना रखी है, उस पर मुझे आश्चर्य है क्योंकि यह है कि सरकारी स्तर पर जो लोग उसमें

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

नामांकित हो कर जाते हैं उनको सहकारिता की भावना का, उसके विचार का, उसमें कैसे काम होना चाहिए, इसका कोई पता नहीं होता। साधारण शेयर होल्डर का भी उसमें हिस्सा होना चाहिए, उसके बजाय आप अपनी पार्टी के सदस्यों को ही उसमें नामीनेट कर देते हैं और जिन लोगों को आपने आज तक उसमें नामीनेट किया है उनको व्यापार का कोई अनुभव नहीं रहा, सहकारिता का जिनको कोई अनुभव नहीं, ऐसे लोगों को ही आपने उसमें चेयरमैन के स्थान पर नियुक्त किया है और उसके कारण ही यह सुपर बाजार आज घाटे में चल रहा है। जो कुछ आपने आज तक उसको ऋण, लोन और शेयर सनो के रूप में दिया है, वह सारी की सारी पूंजी आज समाप्त हो गयी है। आपने यही बताया है कि आपने उसको कितना दिया है लेकिन बैंक से उसने ओवर ड्राफ्ट लिया है या नहीं, इसका पता नहीं और इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुपर बाजार की वर्तमान पोजीशन क्या है, उसकी जमा पूंजी, उस का वर्तमान स्टॉक, बैंक का ओवर ड्राफ्ट और ऋण आदि सब लेने के बाद उसकी क्या स्थिति है और वह कितना घाटे में चल रहा है, इस बारे में माननीय मंत्री जो सदन को जानकारी देने को कृपा करें ?

दूसरे जो व्यवस्था संबंधी बात है, सचिता बहिन आज उसकी चेयरमैन हैं। मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था और उस में उन्होंने कहा है कि अब हम यहाँ पर चीजें सस्ती सेब रहे हैं। दावे वहाँ सस्ती विक रही हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आयी कि सुपर बाजार में चीजें सस्ती विकने के बाद सुपर बाजार का सेल क्यों घट रहा है। आप देखेंगे कि 1966-67 में 478 लाख रुपये का सेल हुआ, 1967-68 में 509 लाख रुपये का सेल हुआ, 1968-69 में 439 लाख रुपये का सेल हुआ और 1969-70 में 391 लाख रुपये का सेल रह गया और इस के बाद के आंकड़े माननीय मंत्री जी बतायेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि प्रति वर्ष का सेल घटता जा रहा है

और इसका स्पष्ट कारण यह है कि जिस उद्देश्य से यह सुपर बाजार कायम किया गया था आज यह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिनको मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए पेश करना चाहता हूँ। 12-7-72 को आज के लगभग एक महीने पहले सुपर बाजार के भाव में और दिल्ली के दूसरे बाजारों के भाव में कितना अंतर था, इसको आप देखें और उसके कारण ही आज ग्राम ग्राम भी सुपर बाजार में जाने के लिए तैयार नहीं होता। तिल के तेल का चार किलोग्राम का टिन सुपर बाजार में 32 रुपये 70 पैसे का विकता था, जो कि प्रेसीडेंट स्टेट के बाजार में और गोल मार्किट में—दिल्ली के सदर बाजार की बात मैं नहीं कहता वहाँ तो इससे भी सस्ता मिल सकता था, लेकिन वह पीपा सोल मार्किट में 27 रुपये 20 पैसे में मिलता था। आप देखें कि कीमतों में कितना अंतर है। ओकलीन का डिव्वा सुपर बाजार में 14.50 का मिलता था जब कि गोल मार्किट में 14.40 का मिलता था। बोर्न बिटा 14.50 का सुपर बाजार में था और 14.30 का बाहर मिलता था। डू काफो 10.45 की सुपर बाजार में थी और 9.85 की बाहर मिलती थी।

MR, DEPUTY CHAIRMAN You need not read out all the pri

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, साधारण चीजों की भी सदन के अन्दर सूचना नहीं दी जा सकेगी कि किस प्रकार से छोटी से छोटी चीज पर भी चाहे वह टेलकम पाउडर हो या कोई और चीज, वहाँ ज्यादा दाम देना पड़ता है। टेलकम पाउडर 4.50 में सुपर बाजार में मिलता है जो बाहर 4.20 में बाजार में मिल जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति थी और यह कहना कि सुपर बाजार की कीमतों को रोकने के लिए, वहाँ चीजें सस्ती मिल सकें, इसके लिये कायम किया गया था तो वह बात तो वहाँ है नहीं, उसे तो सुपर बाजार कहने के बजाय सुपर प्रॉफिट बाजार कहा जाय और उसका नामकरण इस प्रकार बदल दिया जाय तो जनता

को उसके बारे में सही जानकारी हो सकेगी। तो जिस उद्देश्य से सुपर बाजार का निर्माण किया गया था कि चीजों की कीमतें ज्यादा बढ़ने से रोकी जायें, और मुनाफाखोर ज्यादा मुनाफा न कमा पायें, वह समाप्त हो गया है और जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि वहां पर तो अब ठेकेदारों की मार्फत चीजें खरीदी जाने लगी हैं और उनकी बिक्री भी ठेकेदारों की मार्फत होने लग गयी है और जो काम कोऑपरेटिव को करना चाहिए था उसे इंडिविजुअल को देने की बात हो गयी है।

श्री उपसभापति : अब आप खत्म कीजिये।

श्री जगदीश प्रसाद भाथुर : तो इस पद्धति के बारे में कौन सा इनका उत्तर है। दूसरी एक बात है। आपने कहा घाटा हुआ, इसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि पता नहीं किसने यह योजना प्रारम्भ की कि सुपर बाजार खेती भी करे, सुपर बाजार ने भी खेती करना प्रारम्भ किया, कहा कि सब्जी नहीं मिलती है और सुपर बाजार ने खेती करना प्रारम्भ किया, सब्जी उपजाना प्रारम्भ किया और उसमें 6 लाख रुपये का घाटा हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें खास कर के किमका दोष है, किस अधिकारी ने खेती करने का काम सुपर बाजार में प्रारम्भ किया और जो यह 6 लाख रुपये का घाटा है वह किसको देना है।

महोदय, अब तक जो घाटा हुआ है और मंत्री महोदय ने जो इसके लिये कदम उठाये हैं उसके साथ में क्या वह एक ऐसा कमीशन नियुक्त करेंगे जो कि सुपर बाजार में जो घाटा हुआ है उसके बारे में देखे। कोई व्यक्ति या कोई कमीशन की व्यवस्था करेंगे जो कि इसकी जानकारी करे। आपने कुछ स्टेप्स लिये हैं, लेकिन इसके बजाय कोई और व्यवस्था करें, एक कमीशन नियुक्त करें, उसमें आप किसी को भी रखें, कोई कोऑपरेटिव सैक्टर के एक्सपर्ट हों उनको रखें चाहे वह माननीय कुलकर्णी जो हों जो कि कोऑपरेटिव में बड़ा दखल रखते हैं, ऐसे कुछ लोग रखें और वह देखें कि सुपर बाजार के अन्दर क्यों घाटा हुआ, किस कारण से घाटा हुआ ? तो क्या इसकी जांच करवायेंगे

जिससे कि जनता के अन्दर सुपर बाजार के बारे में जो भ्रान्ति फैली है वह दूर हो सके और जो आज यह स्थिति हो गयी है कि सुपर बाजार मुनाफाखोर बाजार हो गया है इसके बारे में स्पष्टीकरण करें।

SHRI ANNASAHAB SHINDE : I have no objection if my colleague, Shri Kulkarni, looks into these matters. I am prepared to seek his assistance and we would welcome if he has any suggestions to make to us to improve the affairs of the Super Bazar.

DR. BHAJI MAHAVIR (Delhi) : Why, Mr. Kulkarni only ?

SHRI ANNASAHAB SHINDE : I said that because he mentioned his name. I am not trying to defend the losses which the Super Bazar is incurring. In fact I said in my statement that every effort is being made to improve the position and to rectify matters. But the way the hon. Member was trying to criticise it was not fair because it had always been the effort of the private sector and the trading community in Delhi to see that the Super Bazar did not succeed. I do not know; there are hundreds and thousands of shops and Super Bazar is one of them but the trading community is always interested in deriding and criticising it and saying that things are sold at higher prices in order to scare away the consumers. We have a very elaborate market intelligence organisation and \ into this and we find that sometimes there are some items. But ultimately the price is related to quality. Simply because a particular commodity is sold at a particular price a hasty conclusion should not be drawn that Super Bazar is selling things at higher prices. There may be marginal commodities where perhaps sometimes the prices may vary from the market rates. I quite concede that point but even on that my information is that this has not happened in 90 per cent of the commodities. In the marginal ten per cent of commodities on occasion this might have happened and this position came to our notice. But the

[Shri Annasaheb Shinde] activities of the Super Bazar have to be understood and appreciated in the proper background. After all this is a movement and this organisation was started in order to give protection to the consumers. We would very much like that this sort of organisation should be in a position to really serve the cause of the community in a much better way. I am prepared to share the concern of the hon. House and the hon. Members. The main issue seems to be the management problems, and because of that there have been some failures, overlooking, for instance is one of the factors. Due to enthusiasm in the beginning a large number of staff was employed and now we find that the Super Bazar is overstaffed. I do not think that the hon. Member should find fault with any particular political party. One of my colleagues—he is not here now and he is sitting in the Opposition nowadays—Mr. S. D. Misra, even when he went to the Opposition, continued to be at the helm of affairs of the Super Bazar and despite his best efforts—he was one of the very notable J co-operators—even he could not help in improving the situation because there are many factors involved. I do not know why the hon. Member should criticise Savita Behcn because she is one of the very experienced politicians; she has had a lot of experience in life and with her at the helm of affairs I anticipate that she will be in a position to draw upon her experience in order to improve the position.

I do not know why you are so allergic to politicians or social workers heading these bodies. In fact, may I submit that I know something of the co-operative movement in India? Sir, I have spent a major part of my life working in the co-operative movement, and co-operative is a field for non-official, not for officials. Even if somebody is associated with a political party, that should not really come in the way of any politician heading,

a particular organisation.

Then the hon. Member, Tyagiji, wanted to know the figures for losses. As I have mentioned in the Statement, from the beginning Super Bazar has been incurring losses and there is no reason why I should conceal this figure. In 1966-67 the loss was Rs. 7,09,000 in 1967-68 it was Rs. 20,70,000, in 1968-69 it was Rs. 19,41,000 in 1969-70 it was Rs. 18,57,000 and in 1970-71 it was Rs. 16,93,000/-. It almost comes to 84 or 85 lakhs of rupees, and this has been the loss even when Shri Shyam Dhar Misra, one of my colleagues who is in the opposition now, was managing the affairs of the Super Bazar. And even one of the members of the hon. Member's party was associated with the Committee of Management for a number of years.

SHRI SUNDAR MANI PATEL (Orissa) : Why don't you make Shri Mathur Chairman of it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : Shri Shyam Dhar Misra was there for three years.

SHRI MAN SINGH VARMA (Uttar Pradesh) : No question of party; he must have business experience.

SHRI ANNASAHAB SHINDE : Do you think that Shri Shyam Dhar Misra was not experienced? Do you mean to say that? As I said, in order to improve the Super Bazar a number of steps which I have enumerated in my Statement are being taken. I myself have just started looking into it. As far as the Department of Cooperatives is concerned, after Shri Pahadia, one of my colleagues, has been transferred to another Ministry, I have taken over charge of the Co-operative Department, and I propose to have a discussion with all the Members of Parliament from Delhi next week, and I would like to have suggestions from any of you because this

is a very desirable movement. The Public Accounts Committee of Parliament has gone into it and they also, while making some comments have said that this is a very vital movement in the interest of consumers. Therefore this needs all the strength and support from this hon. House, from hon. Members, and I would welcome any constructive suggestion. Let us not, in the name of the private sector and vested interests, bring this organisation into difficulties. On the contrary, let it benefit by our goodwill and by our support, and I would like to have constructive suggestions so that I may be in a position to help to improve the working of this organisation.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : Sir, the Minister has given certain background and the measures for improving the working of this organisation. Sir, actually it is not so that all the Super Bazaars are not working well. Some are working well and some are working bad. Therefore, Sir, there cannot be a general condemnation of the Super Bazar movement because, Sir, at the present juncture, when there is the inflation rampant in the country, it is the organisation of Super Bazar in the co-operative field which is really the solution to this problem. Actually I think one or two committees have examined the working of the Super Bazaars in the country in the light of the experience of the Delhi Super Bazar and so, Sir, may I know from the Government whether it is a fact that the whole trouble starts in your internal distribution system in the distribution of the consumer items ? The Government particularly the Ministry of Cooperation in the Central Government, has to be very careful and see that the internal distribution of the consumer items is properly arranged. Through your weak administra-

tive structure and financial structure there you are exposing it to compete with the organised sector in consumer items. There in the organised sector, of course credits are given. In the Super Bazar you cannot give credit. These are internal organisational defects, and if you want to work the Super Bazar properly, you will have to behave as a commercial organisation, and for that purpose would you take steps that the Super Bazaars, whether in Delhi or elsewhere in the country, will get all the consumer items including those which, though not controlled in the strict sense of the term, are very sensitive to the fluctuating situations, and supply them to the consumers at a very reasonable rate ? So that the Super Bazar may work properly. Secondly I want to know, leave aside the injection of politics, etc. into it. Politics have nothing to do with it. If there is honest entrepreneurship and if there are honest men controlling it, they can work anywhere in the Super Bazar in a healthy way and it will be always useful to the community. For that purpose I really do not know whether the Central Ministry is to be blamed, because ultimately it is the State-level administration which has to control the working of the Super Bazar. For that the failure of the Super Bazar is not exactly at the Government level. On the contrary it is at the level of us who are organisers. We have misused our position. It is no use blaming the Government. Apart from the failure of the co-operative organiser, it is also a fact that the responsibility and the share of the Government is not a small one. The entire streamlining of the Super Bazar administration in the co-operative sector has to be undertaken by the Government. Unless positive steps are taken platitudes like reducing the administrative expenditure are not going to solve the problem in the long perspective.

[SHRI A. G. KULKARNI]

On these two counts, unless the Government takes action, the Super Bazar administration is not going to improve.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I am thankful to the hon. Member for the various suggestions he has made. Government would not like to shirk its responsibilities as far as the Super Bazar is concerned. Personally I feel that in the present drought situation and the price increase a consumer's organisation and an institutional framework like this will go a long way in protecting the consumer. Therefore, these organisations have got relevance in the present context and also in the long run. As the hon. Member has rightly pointed out, when we work in competition with the organised sector and established trade naturally this type of organisations have certain difficulties. As the hon. Member himself is aware, we have been trying to organise the consumer's co-operative movement. Certain consumers' co-operatives are coming up very well, but there are some which are blacksheep, but by and large they are coming up very well. As far as the Delhi Super Bazar is concerned, I crave the indulgence of the House that we may be given some more time. I look forward with confidence to the future and I hope we shall be in a position to improve

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं किसी को जिक्र करना नहीं चाहता हूँ और मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे मित्र श्री कुलकर्णी ने यह जो कहा कि इसमें सरकार का दोष नहीं है इसमें हम लोग जो हैं, वे जिम्मेदार हैं, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। श्री कुलकर्णी जी इस बात को मानेंगे कि अगर किसी व्यवसायी संस्था को लाभ होता है तो वह किसी कारण से लाभ होता है और इसकी जिम्मेदारी किस की जाती है।

the state of affairs in times to come.

दिल्ली के सुपर बाजार को पिछले सात, आठ सालों से जिस तरह से लगातार लाभ होता चला जा रहा है, उसका प्रभाव देश के दूसरे सुपर बाजारों पर भी पड़ रहा है। अभी मंत्री जी ने बतलाया कि दिल्ली सुपर बाजार का इन्वार्ज श्री श्यामधर मिश्र को बनाया गया था, तो मैं यह बात जानना चाहता हूँ कि श्री श्यामधर मिश्र को व्यवसाय की क्या जानकारी थी और उनको कोऑपरेटिव की कितनी जानकारी थी, जब वे इन्वार्ज बनाये गये थे।

श्री ए० जी० कुलकर्णी : वे मिनिस्टर रह चुके हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : जरा आप मेरी बात सुन लीजिये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं भी कंजूमर कोऑपरेटिव सोसायटी चलाता हूँ और पिछले 10-15 सालों से चलाते आ रहा हूँ और उसमें किसी तरह का लाभ नहीं होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली के सुपर बाजार को भी कोई लाभ नहीं होगा अगर मुझे चलाना हो। मैं फिर कहना हूँ

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : दीजिए इनको मौका।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे चलाना हो तो कोई लाभ नहीं होगा। क्यों लाभ हो रहा है मंत्री जी इस पर गौर करें। जिस समय सुपर बाजार को संगठित किया गया उस समय इसको बहुत टाप हैवी बनाया गया, एड्मिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज बहुत ज्यादा रखे गये, यह सोचा ही नहीं गया कि वह व्यावसायिक संस्था है, यह गौर नहीं किया गया कि इसमें मुनाफा कितना निकलेगा। इसका खयाल नहीं रखा गया कि कितना खर्चा लगा रहे हैं और कितना आ सकता है। यह समझ कर इसको बनाया गया कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट आफ इंडिया का रुपया है और दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ सुपर बाजार बनाए गए—मुझे याद है वहाँ से

एक बड़े सीनियर अफसर साहब, मिस्टर चटर्जी भेजे गए पूरे देश में, लखनऊ गए थे, इलाहाबाद गए थे, हर जगह उन्होंने जा-जा कर कोशिश करके सुपर बाजार खुलवाए, उनको चेक किया, देखा—हर जगह वही माहौल है, जो दिल्ली में हुआ वही लखनऊ में हुआ, वही इलाहाबाद में हुआ, कहीं 20 लाख का, कहीं 30 लाख का और वही 35 लाख का बोस है। श्रीमन्, इसमें प्रमुख कारण यह है कि जिस समय ये स्थापित किए गए उस समय कतई यह नहीं सोचा गया कि कितने लोग इस काम में लगाए जायें, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रखा जाय, बल्कि पोलिटिकल आधार पर तमाम लोगों को उसमें भरा गया कि उनको रोजी मिल जाय, जिस किसी की सिफारिश पहुंची उसको एम्प्लॉयमेंट दे दिया गया। उसके कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और बकिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरा कारण—मैं आपको बताता हूँ—यह है कि कुछ अधिकारियों ने लम्बी-लम्बी रकमें बनाई हैं सुपर बाजार के अन्दर, किसी ने 5 लाख कमाया है, किसी ने 10 लाख कमाया है। और मैं शिन्धे साहब से कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि वे कोई इन्क्वायरी कमेटी बैठाने तो मैं साबित करूंगा कि अफसरों ने 10-10 लाख रुपये कमाए हैं सुपर बाजार से। एक छोटा उदाहरण सुन लीजिए। इलाहाबाद के सुपर बाजार में 5 लाख रुपये का तोलिया एक बार खरीदा गया गोरखपुर के एक हैन्डलूम के बिजनेसमेन से और वह तोलिया जब नहीं बिका तो जांच शुरू हुई कि क्यों ऐसा हुआ तो मालम यह हुआ कि रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव की सिफारिश पर सुपर बाजार के इन्चार्ज जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं मिया सिद्दीकी ने इस्क्लोज किया मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा, मैं क्या करूँ, मुझसे कहा गया खरीद लो।

श्री उपसभापति : यह प्रश्न है दिल्ली सुपर बाजार के बारे में।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आप और करें कि जितने सुपर बाजार हिन्दुस्तान भर में हैं सबका

रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दिया है। आपको, श्रीमन्, मालूम नहीं होगा।

श्री उपसभापति : मैं जानता हूँ। आप दिल्ली सुपर बाजार के बारे में बोलिए।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं दिल्ली पर ही आ रहा हूँ। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। यह कहना कि सरकार के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं है, यह सही नहीं है। सरकार ने सुपर बाजारों की व्यवस्था इन ढंग से की कि उनके अन्दर सारा काम अफसरों के सिपुर्दे कर दिया। नान-आफीशियल्स को केवल नाम के लिये रख दिया। सारा अधिकार और सारा इन्तजाम आफीशियल्स के हाथ में था। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अफसर और दूसरे अफसरों ने लम्बी-लम्बी रकमें बनाई और यह कहा गया कि इसमें कन्ज्यूमर की बातें थीं इसलिए हो गया। कन्ज्यूमर के लिहाज से भी जहां कुछ आइटम्स में भाव के उतार और चढ़ाव की वजह से घाटा होता है, वहां दूसरे आइटम्स में फायदा भी होता है और दोनों का प्रभाव जब पड़ता है तो घाट का प्रश्न ही नहीं आना चाहिये। प्राइवेट व्यवसायियों में भी सही है। उनको जब कुछ आइटम्स में भाव के उतार-चढ़ाव के कारण घाटा होता है तो दूसरे आइटम्स में पूरा कर लेते हैं। तो, श्रीमन्, मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसमें सविता बहिन का कोई दोष नहीं है, मगर आपने जो व्यवस्था कर रखी है अधिकारियों की उस व्यवस्था को बदलने की बात आप सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? उस व्यवस्था में जिम्मेदारी फिक्स करने की बात आप सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? हम जहां रन करते वहां हर आदमी की जिम्मेदारी हमने फिक्स कर रखी है जिस आइटम में, जिस थाप में लोस होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपकी पे से काटा जायेगा, आपको बाहर किया जाएगा नौकरी से। क्या आपने इस तरह की कोई जिम्मेदारी फिक्स करने की कोशिश की है? अगर आप इस जिम्मेदारी को फिक्स करें तो कल से लोस होना बन्द हो जाय।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : About some of the suggestions of the hon. Member about fixing up personal responsibility, etc., Shrimati Savita Behen is here and she will be taking note of them. Then the hon. Member made an accusation, a statement, that some people have made money. If he has any information about it, I will be glad to receive that information. If there are any particulars, I will be glad to instruct the Department to go into these matters and if somebody has misused his position and has tried to profit as a result of his association with the Super Bazar, it will be looked into, and so far as the Government of India is concerned, we have no interest in protecting anybody if some body has misbehaved in these matters.

...(In

terruptions)

SHRI NAWAL KISHORE : Except the Chairman of the F.C.I.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I

think you discussed the Food Corporation yesterday.

SHRI NAWAL KISHORE : You were absent.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I was not absent, but I was busy in the Lok Sabha.

The hon. Member made a reference—, in fact, I did not deliberately mention what Shri Kulkarni mentioned—to the non-official character of the movement. I think in this country the cooperative movement in certain parts is not coming up well. There are two reasons, to my mind, for that—too much dependence on Government official machinery; in some places, there is even too much interference from the Government. It should be necessarily a non-official movement led by non-officials and organised by non-officials. Therefore, Shri Kulkarni was referring to that aspects. And in this country ultimately co-operators and non-officials will have to take the responsibility of leading the movement and

organising this movement. To much dependence on Government machinery will never be helpful so far as the cooperative movement is concerned. It is all right—Government's duty is to help and assist the cooperative movement, to render financial assistance where necessary. But ultimately the future of the cooperative movement in India including the Super Bazar lies in non-official leadership and in a non-official initiative.

As far as some of the other points raised by the hon. Member are concerned such as over-staffing, the high rate of rent, reducing the pilferage rate, etc. all these points have been looked into. And Government's effort is now to see that pilferage is reduced further. From 3 per cent to 1 per cent it has come down. But even 1 per cent is not justified. I quite see that. But we are taking the necessary steps to improve the state of affairs.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आप जिम्मेदारी फिकस करने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I have said that Shrimati Savita Behari would take note of it.

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : श्रीमान्, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सुपर बाजार की जरूरत है। हो सकता है कि कुछ लोग इस बात से सहमत न हों, लेकिन हम इस बात से सहमत हैं कि सुपर बाजार की जरूरत है। सिर्फ इसमें मतभेद इस बात पर है कि सुपर बाजार को किस तरह से चलाया जाय। सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि सुपर बाजार जैसा कि मंत्री जी ने रिपोर्ट पेश की घाटे का विषय रहा है। अभी तक सुपर बाजार में 86, 87 लाख रुपये का घाटा हो चुका है। इसका कारण क्या है कि सुपर बाजार में इस तरह का घाटा होता है। हम को जो थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी है वह यह है कि ग्राम तौर पर यह पाया जाता है कि जब कोई पब्लिक कंसर्न और प्राइवेट कंसर्न साथ-साथ चलता है तो पब्लिक कंसर्न

की बहुत सी चीजें चोरी हो कर के प्राइवेट बाजार में बिकी जाती हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सही है कि हर साल सुपर बाजार से उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, वे उसका माल चुरा कर के उसको प्राइवेट बाजार में बेच दिया करते हैं। गत साल जब सरकार ने अपने माल की स्टॉक चेकिंग की तो क्या सरकार ने इस तरह की चीजों का कोई पता लगाया और अगर पता लगाया तो कितनी रकम की चीजें इस तरह से प्राइवेट बाजार में गईं। दूसरी बात जो इस संबंध में मैं जानना चाहूंगा वह यह है कि अभी तक जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो प्राइवेट लोग, जो काम करते हैं और जो उस में सरकारी अफसर हैं उनके बीच में क्या रखा है? क्या उसमें गैर-सरकारी लोगों की संख्या ज्यादा है एडमिनिस्ट्रेशन में या उसमें सरकारी लोगों की संख्या ज्यादा है?

तीसरी बात जो मैं जानना चाहूंगा वह यह है कि पब्लिक कंसर्न में एकाउंटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है और उनमें एकाउंटिंग बहुत ही प्रामिनेंट पार्ट प्ले करता है। जब प्राइवेट लोगों से पब्लिक के हित में कोई चीज आती है तो वहां एकाउंटिंग एक गंभीर सवाल बन जाता है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या एकाउंटिंग एक्सपर्ट्स सुपर बाजार में ऐसे रखे गये हैं कि जो एकाउंट्स को अच्छी तरह से मॉनिटर करते हैं और सरकार को घाटे और मुनाफे की खबर होती है, ताकि वहां की चोरी को ठीक ढंग से पकड़ा जा सके?

SHRI ANNASHEB SHINDE : Sir, there is a Financial Adviser now of the Indian Audit and Accounts Service with the Super Bazar. He guides the accounting procedures etc.

As far as the point of pilferage is concerned as I mentioned earlier, the pilferage was very large in the beginning; it was

, almost between 21—3 per cent. Obviously some members of the staff were also involved in this. Necessary action has been taken against them. But now, as I was submitting the pilferage is reduced; it is round-about 1 per cent. Our effort would be to reduce it further.

As for the deputationists they are few in number. They are only in key positions. But most of them are the recruited staff of the Super Bazar.

SHRI SUNDAR MANI PATEL : I am thankful to the Minister because he revealed the total loss incurred by the Delhi Super Bazar. Besides this, may I know the total investment by the Government on the Delhi Super Bazar in (the shape of grants, loans and shares)?

In this connection I want to make an observation. The hon'ble Minister has submitted that actually these organisations should be run by private persons and the organisations should not be dependent on the Government. But that is not enough to check the failures of the co-operative movement. Now-a-days co-operative organisations are politically oriented. Otherwise the hon'ble Minister would have accepted the challenge which was given by my colleague, Mr. Shahi. Such an organisation should be free from political bias. It should be free from...

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat) : Political patronage.

SHRI SUNDAR MANI PATEL : political bias. Unless you change your attitude we are not going to achieve success in the co-operative movement. Will the hon'ble Minister accept the offer of my friend?

Mr. DEPUTY CHAIRMAN : There is already a chairman who has just come in .

SHRI ANNASAHEB SHINDE : The contribution of the Central Government to the Super Bazar is by way of share capital. The total amount that has been contributed is Rs. 1.45 crores all-told, share capital and other loans and other assistance. I do not think he is correct in this conclusions that it is mainly with the idea of political patronage that people have been put there. I may read out the list of members nominated by the Government. They are :—

1. Shrimati Savita Behen
2. Dr. (Mrs.) Durga Deulkar
3. Shri Balrai Khanna, Deputy Mayor, D.M.C.
4. Shri V.V. Ajmera
5. Shri M.M.K. Wall, Secretary, N.C. DC.
6. Shri M.W.K. Yusufzai, President, N D.M.C.
7. Registrar Co-operative Societies
8. Chief Director, consumer co-operatives Department of Co-operation, Min'Stry of Agriculture.

Most of them represent the various Departments of the Government and other institutions. It is not correct to draw any blank conclusion that these organisations i are run with a view to giving political pat- je to anybody.

SHRI G. A. APPAN (Tamil Nadu) : | May I know from the hon'ble Minister i whether there is perfect costing system for [every department or branch of the Super Bazar. You know, the techniques of mar-keting, salesmanship, etiquette, manners, [principles, etc. are imparted by proper i training. But I do not know how far the I

people rocruitted now for work in the Super Bazar have been trained in these professional techniques. May I also know whether the demand and supply had been properly assessed * And what is lhc percentage of the working capital and the inventory ? There should be a percentage ratio between the working capital, the in-inventory, the turnover and all these things. May I also know whether the profit and loss account is being worked out every month ? You know if ii is left for a year, we will not be able to make any check. I have known, in my marketing experience in my salesmanship experience, that even big department stores and workshops have been maintaining accounts of day-to-day stock and day-to-day sales. They have also been working out month-wise profit or loss. If these things had been done, we could have averted loss and advised the particular department or branch or section to see that they work properly. The hon. Minister has stated that the losses are Rs. 80 lakhs and more in the past few years, whereas the capital "nvested, according to the hon. Minister, is only Rs. 1.35 crores. After having invested Rs. 1.35 crores, they have incurred a loss of Rs. 80 lakhs and odd. I do not know when we will be able to wipe off these losses. In this context, I would like to know the number of co-operative organisations that our honourable present Chairman has managed so far. I would also like to know whether it is not possible for the hon. Minister to appoint a parliamentary committee, consisting of Members from both the Houses, to look into the affairs of the Super Bazar and submit a report to the Government within a month or so. May I also know the perquisites, the salary and allowances, given to the Chairman now...

SHRIMATI SAVITA BEHEN (Delhi) :
Nothing.

SHRI G. A. APPAN :... and to (he Directors there ? I want the Directors and Chairman to work in an honorary capacity, and full time. Parliamentary work is a full-time work for a Member. I do not know how a Member of Parliament can also find time to cook for her children, husband and family and to devote some time there also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Just as you find time to go to your constituency.

SHRI G. A. APPAN : I have no axe to grind against anybody. I am working in the best interests of the economy of the country.

I would also like to know whether it is not a fact that the prices charged here are sometimes higher than the prices charged elsewhere. Unless you are able to supply every commodity at 5 to 6 per cent less than the market rate, who will come to you ? Under these circumstances, I want categorical replies to all my questions.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Sir, I am thankful to my friend Mr. Appan, but he made a long speech and expressed his opinion, and it is very difficult for me to make out what the questions are. But I will try my level best.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Well, be brief.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Yes, Sir. First of all, I am sorry I cannot agree with him about his suggestion for a parliamentary committee. What can a parliamentary committee do ? As I said, they are mainly managerial, administrative and commercial problems and from those angles, necessary examinations are being made. A parliamentary committee will not help, but if hon. Members want to make any suggestions, as I said earlier, I

am prepared to welcome those suggestions and to see to what extent they can be acted upon. The honourable Member also made a suggestion for (trained personnel. I quite see the point that (trained personnel are absolutely necessary. Some effort is being made to train the personnel. But much more needs to be done as far as trained personnel are concerned. And that is one of the aspects which is engaging the attention of the Super Bazar management. Then, I am sorry Mr. Appan was very unkind and harsh to one of our colleagues because...

SHRI G. A. APPAN : No, no. It does not affect any personality. I submit that it does not affect any personality.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : After all, Sir, she is working in an honorary capacity...

SHRI G. A. APPAN : We do not want honorary people. She has so much work to do. Even we are not able to attend to our parliamentary duties completely. One person should do only one thing at a time. And let that one thing be done well. That is a very good rule. Let everybody do his or her job perfectly, but only one job at one time, rather than putting one's leg in everything.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : It may be Mr. Appan's opinion. But I think Shrimati Savita Behen is rendering a very valuable service. In fact we are thankful to her for spending so much time and energy for the Super Bazar.

Sir, I do not think there is any other point which needs any explanation.

SHRI SHYAMLAL GUPTA (Bihar): As far as my information goes, the losses go up to a crore and a half rupees. The pro-

[SHRI SHYAMLAL GUPTA] cedure for making a balance-sheet is that in the closing stock you include the prices so that the losses are minimised. For example, the price of a blade when they get is 5 paise. But afterwards it might have gone up to 8 paise. So the losses should be much more than Rs. 86 lakhs as disclosed by the honourable Minister. My question is whether the Government will ascertain whether the closing stocks have been taken at the purchase price or at the price prevailing at the close of the financial year. That is one thing. Thj second thing is Savita Behanji and other parliamentarians who have been heading the Super Bazar must be very good social workers, but not good businessmen. Here to run a business organisation you need business talents. Mrs. Savita Behan has to take care of her constituency and has to oblige so many friends. The same is the case with our former Super Bazar managers or directors or whatever they were then. It is my opinion that if you have to run the Super Bazar, it has to be managed by good businessmen who may be hired from the business community. After looking to the parliamentary work, as Mr. Appan has rightly pointed out, they do not have much time left to attend to these other jobs • So my point is your losses can be minimised if parliamentarians are not taken into the managerial work and the managerial talents are hired for these jobs.

SHRI ANNASAHAB SHINDE : [am sorry the honourable Member seems to have a wrong conception. As far as the administration, the management, is concerned, there are administrative officers in charge. These non-officials only help policy formulation, general supervision, etc. They help to guide the Super Bazaar as such. There is a board of management and the chairman only guides the management committee and the Super Bazar j

in general. As far as the day-to-day administration is cocerned, that is looked after by administrative officers. I quite agree with one suggestion which is implied in the honourable Member's question, that persons with some commercial background should be inducted. The what extent they can be inducted into the management, their mangerial skills, accounting and commercial practices, etc., that is a suggestion worth considering.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : Who guides the loss of Rs. 85 lakhs ?

SHRI SHY AM LAL GUPTA : What about my point about the prices of the closing stock, whether those prices arc-taken into account while preparing the profit and loss account '?

SHRI ANNASAHAB SHINDE : All the stocks are taken into account while the profit and loss account is made. Now the Super Bazar is thinking of a three-monthly stock-taking. But when profit and loss accounts are worked out, naturally the prices of stocks in the inventory are taken into consideration.

SHRI SHY AM LAL GUPTA : Are they taken into account at the cost price or the price prevailing at the time ?

SHRI ANNASAHAB SHINDE : The well-established commercial principles are there, Anyway, I will look into this particular aspect.

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, सबसे पहले तो मैं यह नहीं समझ सका कि मुपर बजार के लिए कृषि मंत्रालय को क्यों जिम्मेदार ठहराया गया है। मैं शिन्दे साहब से सहानुभूति रखता हूँ कि जिस मुश्किल में उनको डाला गया है इन सारे सवालों का जबाब देने के लिए और जो आखिरी सवाल अभी हमारे मित्त ने पूछा

प्राइसिंग कास्ट के बारे में प्राफिट लास के कैलकुलेट करने के बारे में, इस तरह के सवाल के लिए वे अपेक्षित नहीं थे। इसी से मैं समझ सकता हूँ कि उनके जिम्मे किसी के बेबी को पकड़ा दिया गया है संभालने के लिए और मैं शिन्दे साहब से चाहूँगा कि बं संभाले रखें जिसका वास्तविक बच्चा हो। लेकिन मैं उनसे यह निवेदन, करना चाहता हूँ कि उनके मन में जो भ्रम है, उसको मैं दूर कर देना चाहता हूँ।

पहली बात मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि एन्सपीरियंसड पोलीटिशियन होना क्या सब कामों के लिए योग्यता दे देता है। मेरे मित्र श्री श्यामधर मिश्र यहाँ पर आज नहीं हैं और उनके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। हमारी बहिन बड़ी भद्र महिला हैं। और उनके वाकी गुणों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन सोमल बर्कर होना या फिर राजनीति का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते एक बिजनेस कंसन को चलाने के लिए कुछ तरह के नियमों को पालन करने के लिए तथा उनकी जानकारी रखने के लिए योग्यता दे देता है? सरकार को मालूम होना है कि उनके आफिसर हर काम को करने की योग्यता रखते हैं। ब्योरोक्रेट और पोलिटिशियन्स ये आज के युग में ऐसा जगता है कि हर मर्ज की दवा है और किसी जगह भी उन्हें फिट कर दिया जाय तो वे फिट हो जायेंगे।

श्रीमन्, पहली गलती मुझे सुपर बाजार के काम में यह लगती है कि इस तरह के लोगों के प्रभाव में एक ऐसी संस्था को छोड़ देना जो वास्तव में अपने उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। श्री शिन्दे जी ने कहा कि कीमतों को रोकने के लिए सुपर बाजार ने पर्याप्त काम किया है। मैं उनका ध्यान पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की उस रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूँ, जो 11 अगस्त के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी है और उसके दो-तीन वाक्य में पढ़ कर मुना देना चाहता हूँ।

"The Public Accounts Committee has characterised as a tall claim that the Super Bazar, New Delhi, is holding the price line. It is found from data collected that the Super Bazar prices of 11 RSS/72-5

quite a few consumer goods are consistently—(I repeat 'consistently') higher than the market prices."

It observes :

"Admittedly the prices of the store are not competitive any more. The average mark of the sale price over the purchase price has been increased by the store progressively from 10 to 13.5 per cent....."

इस तरह से वहाँ पर स्टोर ने 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 13½ प्रतिशत तक दामों पर चीजें बेचीं।
contrary to the expected reduction from 10 to 8 per cent.

स्टोर से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह 10 प्रतिशत से भी कम दाम पर जनता को सामान बेचता, लेकिन उसने 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 13½ प्रतिशत तक दाम पर सामान बेचा।

श्रीमती सविता बहिन : यह आपके जमाने की बात होगी।

डा० भाई महावीर : 11 अगस्त, 1971 की रिपोर्ट है, पुरानी और नई का मुझे पता नहीं है। अगर आप यह साबित कर देंगी कि 11 अगस्त, 1971 के बाद सुपर बाजार का कार्याकल्प हो गया है तो हम से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। हम संतुष्ट हो जायेंगे दिल्ली वासी संतुष्ट हो जायेंगे कि बहिन जी के जमाने में वहाँ पर जमीन सामान का फर्क आ गया है।

SHRI A. G. KULKARNI : The Public Accounts Committee report usually relate to the previous two years as was rightly pointed out by Shrimati Savita Behen. But I do not claim that it has improved. I do not claim anything. But I am only drawing your attention to this.

डा० भाई महावीर : कुलकर्णी जी पिछले 5 सालों के जो लोसेज बताए गए हैं उन लोसेज में पिछले साल का जो घाटा है वह भी 17 लाख के करीब है, 16 लाख

[डा० भाई महावीर]

93 हजार। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की पिछले एक वर्ष की इस रिपोर्ट के बाद अगर कोई बातें आई हैं तो बताई जाएं हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन मैं केवल यह कह रहा हूँ कि पिछले साल तक तो आप दावा कर रहे हैं कि कीमतें रोकी गईं यह दावा बिलकुल बेबुनियाद है।

दूसरी बात मुझे इस बारे में यह कहनी है कि आप सुपर बाजार की कीमतों की बात जब करते हैं तो जो 80 लाख का घाटा है वह भी टैक्स पेयर के ऊपर पड़ा है। जो हमारे मित्र श्यामलाल जी ने कहा कि घाटा 80 लाख का नहीं शायद डेढ़ करोड़ का है तो मुझे पता नहीं उनकी जानकारी कहां तक है, लेकिन वहिन जी को इतनी जानकारी होगी कि इस घाटे के अलावा 70 लाख का ओवरड्राफ्ट है सिन्डीकेट बैंक का जो आज नहीं तो कल घाटा ही बनने वाला है। अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं गवर्नमेंट के नाम पर लोन नहीं ओवरड्राफ्ट है, जब आप रिपे नहीं कर सकेंगे तो वह घाटे में आ जायगा, तो मैं जानना चाहता हूँ महोदय, कि टैक्स पेयर के ऊपर यह बोझ जो पड़ने वाला है क्या यह शामिल नहीं करना चाहिए? टैक्स पेयर से पैसा लेकर घाटा देना इससे तो जो सुपर बाजार चल रहे हैं उनसे हमें चीजें और मंहगी मिल रही हैं। यह शामिल करके फिर हिसाब लगाना चाहिए कि वह अपने काम को पूरा कर पाये हैं या नहीं।

इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि एक और पहलू में गवर्नमेंट की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ एक महकमा सुपर बाजार बनाता है और चलाता है और गवर्नमेंट का ही दूसरा महकमा उसको डिमोलिश करने की बात करता है। पटेल नगर के अन्दर जो सुपर बाजार है वह 16 लाख रुपए की लागत से बनाया गया और अब डी डी ए उसको फाइनल नोटिस दे चुकी है कि उसको गिरा दिया जाय, डिमोलिश कर दिया जाय। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या डी डी ए कन्ट्रोल करने वाला और सुपर बाजार बनाने वाला गवर्नमेंट का एक ही महकमा, एक ही मिनिस्ट्री नहीं है? प्रेस की रिपोर्टें यह है कि डी डी ए और सुपर बाजार का जो टुल हो

रहा है उसमें whichever side wins, the citizens will lose. क्योंकि अगर डिमोलिश कर दिया तो 16 लाख रुपया जो खर्चा हुआ है—वह रुपया सरकार का कहा जाता है, लेकिन वह रुपया गरीब टैक्स-पेयर का है, सरकार के पास और कोई रुपया नहीं होता, सरकार के पास टैक्स-पेयर का रुपया होता है—वह जाएगा और अगर सुपर बाजार बना रहने दिया गया तो फिर डी डी ए को अपना मार्फिट कम्प्लैक्स बनाने के वास्ते दूसरी जमीन खरीदनी पड़ेगी जो लाखों-करोड़ों की आएगी, दूसरे शब्दों में जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर बोझ पड़ेगा। सरकार की योजना के अन्दर जो इस तरह की धांधली चल रही है, क्या उसका आपको पता नहीं है? क्या मंत्री जी ऐसे समन्वय की कमी लेकर आफ कोऑर्डिनेशन को ठीक करने के लिए कुछ करेंगे?

आपने ओवर-स्टाफ होने की बात कही। आपने माना है कि उसमें स्टाफ बहुत ज्यादा है, आपने कहा कि पहले हजार के करीब था और अब 850 या 835 है। इतनी कमी होने के बाद भी आप मानते हैं कि स्टाफ जरूरत से बहुत ज्यादा है। जो पिलफरेज को रोकने की व्यवस्था है, उसमें स्टाफ की अक्षमता सबसे बड़ा घाटे का कारण है; क्योंकि घाटे की वजह से...

श्री उपसभापति : आप प्रश्न पुछिए, उदाहरण मत दीजिए।

डा० भाई महावीर : क्या यह व्यवस्था नहीं है कि सुपर बाजार में कि अगर अन्दर से कोई 125 की साड़ी लेकर उस पर 25 रुपये की स्लिप लगाए आ रहा है तो गेट का चौकीदार उसे चैक नहीं कर सकता वह ठीक चीज ले जा रहा है या गलत चीज ले जा रहा है? पिलफरेज को रोकने का आज तक जो प्रबन्ध है वह इतना असुविधापूर्ण है कि वास्तव में वह सबसे बड़ा घाटे का कारण है। जब आप यह कहते हैं कि मुझे पता नहीं ट्रेडर्स क्लासेज खिलाफ हैं सुपर बाजार के तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एक प्रयत्न है अपनी कमियां

को, असमताओं को या असफलताओं को छिपाने का और किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराने का, हम समझते हैं कि हमने अपने आपको बचा लिया। इस सूरत में...

1. P. M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : This is a Calling Attention Motion. But you are making it a debate. You have taken 10 minutes to put a clarification.

डा० भाई महावीर : मैंने अकेले ज्यादा समय नहीं लिया और सदस्यों ने भी लिया है। वैसे मैंने कहा कि मैं समाप्त होकर रहा हूँ। (*Interruption*) आपने किसी और को नहीं रोका। मालूम नहीं मुझ से क्यों शिकायत है।

श्री उपसभापति : मैंने मि० आपन को टोका, कुछ और सदस्यों को टोका और उसी तरह से आपको भी टोक रहा हूँ कि टाइम का भी कुछ खयाल रखिए।

डा० भाई महावीर : मैं आखिरी दो तीन वाक्य कह रहा हूँ। पिलफिरेज को रोकने की व्यवस्था अभी तक अधूरी है। इसको ठीक करने के लिए आपने अभी तक वास्तव में कोई प्रबन्ध किया है या नहीं, यह जानना चाहूँगा। इसके साथ-साथ यह सच है कि नहीं कि यह जो 70 लाख का ओवरड्राफ्ट है यह आपके इनवेस्टमेंट में शामिल नहीं हुआ है। मेरी जानकारी में यह है—यलत हो तो बता दोजिएगा—कि कम्पलीट स्टॉक टेकिंग आयद सुपर बाजार की बहुत कम हुई है। यह मैं जानना चाहूँगा कि फिजिकल स्टॉक टेकिंग में यह जो 70 लाख का ओवर ड्राफ्ट है, क्या इसको भी आपने अपने इनवेस्टमेंट के अन्दर शामिल किया है; क्योंकि वह भी सरकारी बैंक है।

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Sir, I am sorry that though Dr. Bhai Mahavirji is a very knowledgeable Member, yet he even does not know that the Department of Co-operation is a part of Krishi Mantra-laya. He made a very long statement and raised a number of points.

I would first of all go into the overdraft problem. The overdraft which the Syndicate Bank has sanctioned to Super Bazar is now being availed of for Rs. 35 lakhs, and not for the amount as mentioned by the hon. Member. Moreover, it is on hypothecation of goods. Actually, Sir it is related to the goods which are in the possession of the Super Bazar.

Then, Sir, the hon. Member stated that Super Bazar is making at all claim about holding the price line. I do not think that Super Bazar is making that sort of claim...

DR. BHAI MAHAVIR : I quoted the PUC...

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Why don't you listen to me ? Ultimately, the prices are a larger economic phenomenon. A number of factors go into the price level—monetary expansion, availability of goods, agricultural production and so on. AH that Super Bazar has been claiming is that it is a pace setter in the prevailing set of circumstances. If the Super Bazar sells commodities or goods at a reasonable price, naturally there is some restraint on the trading community. And it is to that extend that the Super Bazar or any consumer store or, as a matter of fact, any consumer movement for that matter, can claim credit. As a matter of fact, in India the consumer movement is not so powerful. But certainly it is a pace setter for prices, and it has a sobering effect. I am sorry that Dr. Bhai Mahavir, my colleague, always finds fault with the Super Bazar, but not with the private traders. He thinks that the only guilty organization is the Super Bazar and there is nothing wrong with private trading as such...

DR. BHAI MAHAVIR : But it is the Super Bazar which is making a tall claim not the private traders...

SHRI ANNASAHEB SHINDE : But the private traders have many ways' and means; I need not go into all these. I do not want to state all these things.. *(Interruption)*. Some of the traders—not all, but some traders—evade sales-tax. The Super Bazar cannot do that. So there is no full comparison between the two. You are very knowledgeable Member you can understand the implications of this. I am not trying to defend it.

Sir, in the beginning I explained that there are many factors which are contributing to its losses. Pilferage is one of them. But effort is being made to reduce the pilferage also. Effort is being made to improve the administration. Different commercial norms are being employed. All these points are being looked into. But if there are some exceptions, and the Super Bazar prices in a few cases are higher, I do not think it is justified to make a general statement that the Super Bazar prices are higher. I do not think it is justified.

DR. BHAI MAHAVIR : Let me only point out that what I was quoting was from the Report of the Public Accounts Committee. If you have any quarrel with it, you have it out with the PAC.

SHRI ANNASAHEB SHINDE : I am not having any quarrel. I want only to say that it would not be right to make a tall claim that Super Bazar is the only instrument to check the prices because price variation is the result of many factors, economic and others. Super Bazar can only set the pace, set a certain trend in the economy. That is the only humble submission that I am making.

DR. BHAI MAHAVIR : Sir, has he answered my questions ?

I

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Sir, I seek your protection. Hon. Members make long speeches and I am supposed to reply within a limited time. I take up some important items and go into them in detail again hon. Members will complain. To my mind it is right in saying that in Calling Attention Notices only some questions should be put and we should be asked to give replies to these questions. If hon. Members make long speeches we are helpless and we need your protection.

DR. BHAI MAHAVIR : I asked about the demolition of Super Bazar in Patel Nagar. Is the DDA threatening to demolish the Super Bazar ?

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Some problems of legality are under discussion, but not threat of demolition.

श्रीमती सविता बहिन : डिप्टी कमिशनर साहब, एक घंटे से ज्यादा हुआ सुपर बाजार के ऊपर डिपेंड था वहीं है। कॉलिंग अटेंशन डिपेंड बन गया। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी कुछ भाइयों ने सही तरीके से विस्तार दिया। लेकिन मैं पहले अपनी बात कहूँ। कहा जाता है कि मुझे कोऑपरेटिव का कोई तजुबा नहीं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे कुछ 19 साल कोऑपरेटिव चलाने का तजुबा है। 1953 से मैंने उसमें काम करना शुरू किया था और मैं लगातार उनको चला रही हूँ और व्यापार को चलाने का मुझे 22 साल का तजुबा है। मैं अपने घर का बिजनेस सारा अपने आप ही चलाती हूँ। मेरे लिए जो परमनन्त बात कही गयी उसके बारे में मुझे सिर्फ यही कहना है। *(Interruption)* मैंने साथ के बीच में गहो बोला मैं आपके जरिये दरखास्त करूँगी कि बीच में मुझे न टोका जाय। मेरे भाई श्यामलाल जी ने कहा कि मेरी कॉन्स्टीट्यूएँसी है। वह बिहार के किसी हिस्से से आयें हैं। वह राज्य सभा के आनरेबिल मेम्बर हैं, लेकिन मेरी कोई कॉन्स्टीट्यूएँसी नहीं है, मेरा कोई एरिया नहीं है। मैं तो राज्य सभा में मेम्बर के जरिये चुन कर आयी हूँ, इसलिए मुझे किसी खास

इलाके में बैठ कर काम करने की जरूरत नहीं। चूंकि यह बातें मेरे बारे में कही गयी थीं इसलिए मैंने उनका जवाब दिया।

एक तरफ मेरे भाई कहते हैं कि सुपर बाजार में लोसेज होते हैं, मैं उसके लासेज को जस्टीफाई नहीं करती। और करना भी नहीं चाहिए मैं लगातार फाइंट कर रही हूं कि इसलिए कि लासेज को खत्म किया जाय। मैनेजिंग कमेटी डिटरमिन्ड है कि हम लासेज को नहीं होने देंगे, लेकिन उसके साथ ही हमारे भाई यह कहते हैं कि वहां कीमतें बहुत ज्यादा रखी जाती हैं, कम नहीं की जाती। वहां बाजार से ज्यादा दाम लिये जाते हैं। तो बाजार से चीजें हम खरीदें और दाम कम करके बेचें और उसके साथ ही इतना स्टाफ भी रखें और सारा दूसरा इंतजाम भी किया जाय और उसके बाद लासेज भी न हो, तो यह सब तो नहीं चल सकता। पैसे का काम पैसे से ही चलेगा और किसी तरह से नहीं चलता। मेरे आने से पहले। (Interruption)

डा० भाई महाबोर : मैं आपकी बात काटना नहीं चाहता, लेकिन सुपर बाजार बनाया इसी लिए गया था कि कीमतों को बढ़ने से रोका जाय। क्या आप वहां कीमतें बढ़ा कर वहां का घाटा कम करेंगी?

श्रीमती सविता बहिन : I am coming to that सुपर बाजार इसी लिए बनाया गया था कि प्राइज राइज को चेक किया जाय। जब डिबेल्युएशन हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह एक बात सीची कि चीजें लोगों को सस्ती मिल सकें और इसलिए वह एक दम से शुरू किया गया था। और एक दम से जब कोई चीज शुरू की जाती है तो उसमें बहुत सी चीजें सिस्टेमैटिक ढंग पर नहीं हो पाती। शुरू में जो बहुत सी चीजें चलीं वह आगे नहीं चलीं और बहुत सी बातों में मैं आपसे एग्री करती हूं, लेकिन वहां लगातार चीजों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। पहले जो हम सप्लाय लेते थे, सामान खरीद करते थे वह बाजार से खरीद करते थे और उन पर फिर काटेंज आदि भी लगता था। अब हमने सफाई करने की मशीनें भी लगाई हैं। अगर हम उसे नो प्राफिट नो लास बेसिस पर चलायें तो भी उसमें कुछ खर्च पड़ जाता है।

लाने का है, साफ करने का है और कुछ बेस्टेज जाता है। उस सारे को देखा कर के प्राइसेज मुकर्रर करते हैं। अब चार महीने से अब मैंने चार्ज लिया है तो मैंने जाते ही पहली चीज यह भी है कि मिडिलमैन का प्राफिट निकाला जाय, डाइरेक्ट सप्लाय जहां तक हो सके, कपड़े की, प्राविजन की, ग्रीसरी की और और सामान की, वह लेने की कोशिश की जाए।

मेरे भाइयों ने कुछ जिक्र किया ठेकेदारों का कि वहां पर ठेकेदार बैठायें हुए हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट पर हमने कुछ जगह दी हुई है, लेकिन वह भी इसलिए दी हुई है कि हैवी लासेज है। एक तरफ तो कहते हैं कि बाजार को कामशियल तरीके से चलाया जाय और दूसरी तरफ कामशियल तरीके से चलाना चाहते हैं तो आप कंट्रिबाइड करते हैं कि कामशियल तरीके से करते हैं। एक-एक कोने का हम किराया देते हैं तो हमने सोचा कि इनको इस्तेमाल किया जाय और जहां कोई कोना खाली पड़ा था वहां जो स्टैंडर्ड की फर्में हैं, ठुकानें हैं उनको ला करके बिठा दिया कि वह चीजें बेचें ताकि हमारा इतना फैलाव भी नहीं हो और जो जगह खाली है जिसका किराया दिया जा रहा है वह भी खाली न रहे, उसका भी इस्तेमाल हो जाय, इसलिए जगह-जगह कंसाइनमेंट पर कुछ लोगों को बिठाया है लेकिन हम उनकी क्वालिटी और प्राइस को चेक करते हैं। लासेज को चेक करने के लिए, लासेज को कम करने के लिए कहा जाता है, तो एक चीज और भी है, मैं उसको बता देना चाहती हूं, कल उसका सवाल भी नहीं न आ जाय, हम कुछ एडवर्टिजमेंट भी लगाना चाहते हैं, जो बाजार के बीच में, सेंटर में हमारी विल्डिंग है उसके बाहर जो भी जगह खाली है वहां चाहते हैं कि कहीं भी कोई जगह खाली हो तो किसी का एडवर्टिजमेंट लगाया जाय, नहीं फर्मों का लगाया जाय अच्छी फर्मों का लगाया जाय जिससे कि चार पैसे आ सकें, सुपर बाजार को फायदा हो सके और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को फायदा हो सके। उस चीज के लिए भी हम कोशिश करते हैं। मैं यह चीज आपकी जानकारी के लिए रखना चाहती हूं कि जितनी भी बाहर की दीवारें हैं उसमें कोशिश की है कि कुछ कुछ एडवर्टिजमेंट लगायें।

फिर उसके बाद पिलफरेज की बात जोरों से आई। ठीक बात है, पिलफरेज था और अब भी है, मैं यह नहीं कहती कि बिलबुल रुका है, लेकिन पिछले चार महीने से लगातार इन सब चीजों के लिए सिर तोड़ कोशिश की जा रही है। आपने कहा है कि पिलफरेज है तो पिलफरेज के लिए भी हम लोगों ने एक तरीका निकाला है—सामान सारा जो वहां पर काम करते हैं हमारे एम्प्लाइज बट लेकर के जो मुबह जाते हैं लिफाफे या पैकेट्स, जिनको मुबह रजिस्टर पर नोट करके ले जाया जाता है और शाम को बाहर ले जाने की बात होती है, अब यह तय किया है कि इस तरह का प्रबंध किया जाय कि वह सारा सामान वहां छोड़ कर जाएं, सामान अन्दर लेकर न जायें, चाहे वह पांच रुपये का हो या पांच पैसे का हो, सामान वहां रख लिया जाए और जब वापस आये तो सामान दे दिया जाय, अन्दर खाली हाथ जाएं और खाली हाथ आयें।

श्री श्याम लाल मुस्त : तुलाजी लेंगे।

श्रीमती सविता बहिन : तुलाजी की नौबत आयेगी उसको भी देखेंगे, उससे भी हटने वाले नहीं हैं। आपका बड़ा स्वागत है, आप जो भी सुझाव देंगे सुपर बाजार को ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसका घाटा कम करने के लिए, लोगों की सेवा में उसको ले जाने के लिए, तो मैं हर समय आपका स्वागत करूंगी।

फिर ट्रेनिंग के बारे में कहा है। ठीक है, अनट्रेड स्टाफ है, उसको जल्दी से भर्ती किया गया, बहुत सा स्टाफ ट्रेड नहीं है और कुछ ऐसा भी होता है कि जब पता चल जाता है कि तनख्वाह मिल जानी है तो अपने तरीके से काम करते हैं, तो उसके लिए भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि रिफ्रेशर कोर्स चला रहे हैं और आज पहला कोर्स सेल्समैन का ढाई बजे से शुरू होगा, एक-एक हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे, फिर उसके बाद और स्टाफ के लिए करेंगे, सभी के लिए करेंगे, सेल्समैन के लिए, हैलपर के लिए, सुपरवाइजर के लिए, मैनेजर के लिए, सबके लिए अलग-अलग कोर्स शुरू किये हैं जिनको कि एक-एक हफ्ते की ट्रेनिंग दे कर के काम में लगाया जायगा। और साथ में उस चीज को

भी देख रहे हैं जैसा कि आपने कहा कि जिम्मेदारी डाली जाय, मैं अपने भाई भाई जी से टोटली मुत्तफिक हूं कि उनके ऊपर जिम्मेदारी ठहरानो है और उसके लिए हमने यह किया है कि नोटिस दिया है जिनका कि सेल कम है, हम इंसेंटिव भी देते हैं, लेकिन जिन्होंने सेल कम किया है उनको नोटिस दिया है, ओ-काब नोटिस दिया है कि बतायें कि सेल्स कम क्यों है और उसमें जो भी कोई भी बड़े से बड़ा, कड़े से कड़ा एक्शन लेना हो उसमें गुरेज नहीं करेंगे।

तो तीन चार बातों को सामने रखकर के काम कर रहे हैं। प्रयत्न कर रहे हैं...

श्री उपसभापति : आप थोड़ा संक्षिप्त कीजिए।

श्री जगदीश प्रसाद माधुर : बहुत लम्बा भाषण हो गया।

श्रीमती सविता बहिन : भाषण नहीं है, सिर्फ बातों का जवाब दे रही हूं।

SHRI SUNDAR MAN! PATEL : Sir, since we are fortunate enough to have this explanation directly from the Chairman of the Super Bazar herself, we should be allowed to put questions to her. Otherwise, the explanation need not be that long.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : But my difficulty is here; none of the Members should then say that this is Calling Attention notice and she did not make a speech in reply. Strictly she is not seeking any clarification; she is actually giving the clarification, and if Members are indulgent, I will ask her to complete it.

श्रीमती सविता बहिन : हमने डिपार्टमेंट के अंदर अपनी मैनेजिंग कमिटी के मेम्बर्स को लगाया है कि वे एक-एक डिपार्टमेंट को चेक करें कि उसमें क्या-क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उनको ज्यादा अच्छी तरह से सप्लाय की जा सकती है, मिडलमैन के प्रॉफिट को कहीं तक ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सकता है। इन सब चीजों को इम्प्रूव करने की और

ध्यान दिया जा रहा है, स्टाफ की बेकिंग के लिए स्टाफ का रजिस्टर देखा जा रहा है और जो कुछ स्टाफ का लेवल हाई है उसको भी नीचे में लाने के लिए स्टाफ क्लियरेंस किया जा रहा है। यह भी गलत बात है कि हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कोई इतना बड़ा है। मामूली सा, महीने का जो रिवाल्विंग एक्सपेंडिचर होता है उसका सिर्फ ओवरड्राफ्ट रहता है। और किसी तरह का ओवर ड्राफ्ट नहीं है। जो हमारे मिनिस्टर महोदय ने जवाब दिया वह बिलकुल सही है कि हमारे पहले के लामेज, पिछले 6 साल के, 83-84 लाख रु० के हैं। उनके लिए हरचद कोशिश की जा रही है कि लामेज न हों।

स्टाफ की बात आई। स्टाफ ज्यादा जरूर था। पहले कुछ स्टाफ शायद मेरे आने से पहले हटाया गया होगा, लेकिन मेरे आने के बाद यह तय किया गया कि एक भी व्यक्ति को हटाया नहीं जाए, लेकिन सर्पलस स्टाफ को निकाल कर ज्यादा से ज्यादा ब्रान्चेज खोल कर वहां लगा दिया जाए ताकि आमदनी हमारी बढ़े और स्टाफ भी बेकार न हो जाए। इन तरह हमारे सारे स्टाफ का बंदोबस्त किया है। अब लामेज की बात होती है तो वहां सेवा की बात होती है वहां लामेज को भी कुछ हद तक बर्दाश्त करना होगा। एक हमारा ड्रम्स का डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को राउन्ड द क्लॉक शुरू किया है, दिल्ली में ऐसी चीज नहीं थी और प्राइवेट कैमिस्टर्स दुकान बंद कर देते थे; क्योंकि उसमें लाम बहुत होता है, कई फार्मिलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, स्टाफ को रात की फैसिलिटीज देना पड़ती हैं—बेड है, चाय है, कन्वेयन्स है, सो मैनी थिंग्स। तो हमने इस बात को देखा और प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहती थी कि कभी भी किसी वक्त दिन या रात में कोई सीरियस केस में मैडिसिन की डिमान्ड हो सकती है और सहज दवाई न मिलने की वजह से जान चली जाए, इस वास्ते सुपर बाजार में, चाहे जो भी दिक्कत हो, यह काम शुरू किया जाना चाहिए। तो हमने सफदरजंग में और कनाट प्लेस में राउन्ड द क्लॉक ड्रग डिपार्टमेंट शुरू किया है, वह बहुत अच्छे चल रहे हैं। वहां भी हमने अपने मौजूदा स्टाफ के अंदर से लोग निकाल कर लगाए हैं। अभी एक ब्रांच हम नेहरू यूनिवर्सिटी में शुरू करने जा रहे हैं, सारा स्टाफ अंदर से निकलवा कर

वहां लगा रहे हैं। इस वक्त सात ब्रान्चेज चल रही हैं आठवीं शुरू करने जा रहे हैं। कुछ सामान भी अपने यहां तैयार कर रहे हैं—अपने यहां मसाले तैयार करने का, चक्की अपनी लगाने का, इस तरह की कई स्कीमें बनी हैं, जो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मकसद यह है कि जितनी जल्द हो सके, आप सब लोगों के कोअपरेशन से, लोगों के दरवाजे तक सुपर बाजार पहुंच जाए, घर-घर लोगों को सही चीज मिले, सस्ती चीज मिले और सुपर बाजार भी फायदे में चले, इस तरीके से सुपर बाजार को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही हमेशा आप जैसे भाइयों का जो मुझाव होगा उसको बहुत मान के साथ अमन में लाया जायेगा। (*Time bell rings*) हमारे भाई बलराज खन्ना उसमें मौजूद हैं, वे बड़ी खुशी से हमारी मीटिंग में हाजिरी लगाते हैं और वे कहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है और उसमें खुशी से शामिल होते हैं। तो हर चीज को अपोजीशन फार सेक आप अपोजीशन ही क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उसके लिए विद ड्यू रेस्पेक्ट कहना चाहूंगी कि यह हमारी मिली-जुली जिम्मेदारी है, यह पोलिटिक्स से अलग चीज है, पार्टी से भी अलग है। यह एक सेवा का इरादा है। इसलिए अपने सामने बैठे हुए साथियों से मैं दरखास्त करूंगी कि जितना कोअपरेशन, जितना सहयोग इसमें दे सकें, जितनी गाइडेंस दे सकें, उतनी ही दिली हमें खुशी होगी।

LEAVE OF ABSENCE TO SHRI M.S. OBEROI

MR. bEPUTY CHAIRMAN : I have to inform Members that the following letter dated the 10th August, 1972, has been received from Shri M.S. Oberoi :—

"As I am away from India I shall feel grateful if a leave of absence is granted to me for a period of three weeks."

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Shri M.S. Oberoi for remaining absent for three weeks from the ! 10th August, 1972 from the meetings of the House during the current session ?

[No, //on. Member dissented]